

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेखा जिला-भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-10/2017 राजस्व वाद

अन्वयान

श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जोशी, (बाम्हण) उम 54 वर्ष निवासी बड़डू हाउस
परबतसर जिला नागौर। -- अपीलान्त

बनाम

ग्राम पंचायत गोकर्णपुरा जरीये संरपच ग्राम पंचायत गोकर्णपुरा पंचायत समिति माण्डल,
जिला भीलवाड़ा। -- रेषपोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत गोकर्णपुरा जो
नामान्तरण संख्या 966 की पुस्त पर पारित किया गया।
अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० गू राजस्व अधिनियम

उपस्थित -

1. श्री शरद कुमार पाटीवाल (अधिवक्ता अपीलान्त)
2. श्री तारा चन्द जैन (अधिवक्ता रेषपोडेन्ट)

निर्णय

दिनांक 28.03.2018

अपीलान्त द्वारा ग्राम पंचायत गोकर्णपुरा के नामान्तरण संख्या 966 पर प्रदत्त आदेश से नाराज होकर यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल में प्रस्तुत की गई, जो वाद अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपीलान्त द्वारा अपील में निम्नानुसार निवेदन किया गया:-

1. अपीलार्थी द्वारा अपील में निवेदन किया कि अपीलान्त ने विधिवत् साधिकार जायज प्रतिफल अदाकर सदभाविक रूप से छोटा पिता सोला गुर्जर से ग्राम सुलिया में स्थित आराजी संख्या 191 रकबा 02.14 बीघा एवं आ०न० 1858/1828 रकबा 6.13 बीघा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2017 से कय कर कब्जा प्राप्त किया जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा विधिवत् नामान्तरण अपीलान्त के नाम पर खोल कर प्रस्तुत किया गया जिसे रेषपोडेन्ट द्वारा बिना किसी जायज एवं वैध आधार के खारिज कर दिया गया जबकि उक्त आराजियात के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया हुआ था न आज भी है फिर भी रेषपोडेन्ट ने गलत एवं अवैध तरीके से उक्त नामान्तरण स्वीकार न कर खारिज करने में भारी विधिक मूल की है।

प्रपंच अधिकारी पदेन

सहायक कलक्टर करेखा अपीलार्थी द्वारा अपील में निवेदन किया कि रेषपोडेन्ट द्वारा जो नामान्तरण खारिज किया गया उस वक्त पंचायत का कोई किसी प्रकार का पूर्ण कोरम मौजूद नहीं था मात्र रेषपोडेन्ट के सरपंच ने अपनेतही आलौच्य नामान्तरण खारिज किया गया जिसका कोरम के अभाव में उन्हें कोई कानूनन हक एवं अधिकार नहीं था इतना ही नहीं आलौच्य नामान्तरण किस दिन दिनांक को खारिज किया गया इसका भी कोई अकन नामान्तरण पर नहीं किया गया है जो उक्त नामान्तरण पर पारित आदेश अपने आप में सदैवपर्यत होना दर्शाता है। उक्त नामान्तरण को पारित करने में रेषपोडेन्ट द्वारा कितनी जल्दबाजी की गई उसका परितय करा देता है। अर्थात् विधि की सम्यक प्रक्रिया का निर्वहन किये बिना नामान्तरण खारिज करने में रेषपोडेन्ट ने भारी विधिक मूल की है।

3. अपीलार्थी द्वारा अपील में निवेदन किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कब्जे का स्थानान्तरण होने की अवधारणा कानूनन की जाती है और निर्विवाद रूप से उक्त क्रय शुदा आराजीयात पर अपीलान्त का खरीद की तारीख से कब्जा चला आ रहा है तो फिर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण खोला गया उसे स्वीकार किये जाना चाहिए था किन्तु रेस्पोंडेन्ट द्वारा तथाकथित रूप से किसी चन्द्रभान द्वारा मात्र आपत्ति करने के आधार पर उक्त नामान्तरकरण को खारिज कराना सर्वथा गलत होकर अवैध है। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति की गई है तो इस हेतु अपीलान्त को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था किन्तु रेस्पोंडेन्ट ने बिना अपीलान्त को नोटिस दिये, बिना सुने नामान्तरकरण खारिज कर दिया जो नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है।

4. अपीलार्थी द्वारा अपील में निवेदन किया कि नामान्तरकरण संबंधी जो प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत धारा 133, 135 आदि में स्पष्ट किये गये हैं कि किसी भी पंजिकृत दस्तावेज के आधार पर यदि कोई खातेदारी अधिकार की आराजियात स्थानान्तरित होती है तो उसका नामान्तरकरण बिना किसी आपत्ति एवं ऐतराज के क्रेतागण के नाम पर कानूनन निर्णित करना होता है किन्तु रेस्पोंडेन्ट द्वारा उक्त प्रावधानों की जानबूझकर अनदेखी करते हुए आपत्ति करता से मिलाभगती एवं दुर्भिसंधी कर उक्त नामान्तरकरण खारिज करने में भारी विधिक भूल की है।

5. अपीलार्थी द्वारा अपील में निवेदन किया कि आलौच्य नामान्तरकरण खारिज होने की सर्व प्रथम जानकारी अपीलान्त द्वारा अन्य आराजीयात क्रय करने के संबंध में उनकी जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण की नकले लेने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 07.07.2017 को सम्पर्क करने पर पटवारी हल्का ने उक्त आराजियात के संबंध में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 966 को खारिज कर दिये जाने की दी। इस पर अपीलान्त ने दिनांक 11.07.2017 को उक्त नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु तहसीलदार करेडा के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 12.07.2017 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की गई। आलौच्य नामान्तरकरण खारिज करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस अपीलान्त को रेस्पोंडेन्ट द्वारा नहीं दिया गया। इसी कारण अपीलान्त को उक्त नामान्तरकरण खारिज करने की कोई जानकारी यथा समय नहीं हो सकी तथा जानकारी होते ही न्यायालय आप में यह अपील प्रस्तुत की गई है नामान्तरकरण खारिज होने की दिनांक से सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 07.07.2017 तक का समय उपरोक्त वर्णित सदभाविक कारणों से काबिल क्षम्य है। इस हेतु दफा 05 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पोंडेन्ट को वजह जाहिर करने का नोटिस जारी किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ताराचन्द जैन ने अधिकार पत्र पेश किया तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। सर्वप्रथम अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील में परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के आवेदन पर विचार किया जाकर मियाद के विन्दु को तय किये जाने हेतु उभयपक्षों के अधिवक्ता की बहस समायत की गई। अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में विवादित नामान्तरकरण के निर्णय की जानकारी दिनांक 07.07.2017 को पटवारी द्वारा नकले प्राप्त करने पर हुई। जिस तथ्य का अकंन दिनांक 12.07.2017 के प्रार्थना पत्र में व्यक्त करते हुए समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इस कारण विलम्ब की सम्यावधि को क्षम्य करते हुए अपील को मियाद में शुमार किया जावे। जबकी रेस्पोंडेन्ट विपक्षी की ओर से इस प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार खडन नहीं किया गया ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलान्त के दफा 05 के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के समक्ष अविश्वास करने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता है। अतः न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में

अधिवक्ता के

अपील में अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट की बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजियात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2017 के खातेदार छोटा पिता सोला गुर्जर से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त करने का निवेदन किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत् नामान्तरकरण अपीलान्त के नाम पर खोला गया जिसे रेस्पोंडेन्ट द्वारा बिना किसी वैध आधार के खारिज कर दिया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान बताया कि अपील समय सीमा के बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।


अपील में प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मेमो के गुणावगुण पर भी विचार किया गया। अपीलार्थी अपने अपील मेमो में यह कथन लेकर आया कि अपीलान्त प्रार्थी ने विधिवत् साधिकार जायज प्रतिफल के छोटा पिता सोला गुर्जर से ग्राम सुलिया में स्थिति आराजी संख्या 191 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1858/1828 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 01.03.2017 से सदभाविक रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा विधिवत् नामान्तरकरण अपीलान्त के नाम पर खोलकर प्रस्तुत किया गया जिसे रेस्पोंडेंट द्वारा बिना किसी जायज एवं वैध आधार के खारिज कर दिया गया। रेस्पोंडेंट ने गलत एवं अवैध तरीके से आलोच्य नामान्तरकरण स्वीकार न कर खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार कब्जे का हस्तान्तरण होने की अवधारणा कानूनन की जाती है और निर्विवाद रूप से उक्त क्रयशुदा आराजियात पर अपीलान्त का ही तारीख खरीद से ही कब्जा चला आ रहा है तो फिर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को स्वीकार किया जाना चाहिये था किन्तु रेस्पोंडेंट ने बिना अपीलान्त को नोटिस दिये व सुने नामान्तरकरण खारिज कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी है।

नामान्तरकरण संबंधी जो प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत धारा 133,135 आदि में स्पष्टतया किये गये हैं कि किसी भी पंजिकृत दरतावेज के आधार पर यदि कोई किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार की आराजियात हस्तान्तरित होती है तो उसका नामान्तरकरण बिना किसी आपत्ती एवं ऐतराज के क्रेतागण के नाम पर कानूनन निर्णित करना होता है किन्तु रेस्पोंडेंट द्वारा उक्त प्रावधानों की जानबूझकर अनदेखी करते हुए उक्त नामान्तरकरण खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 966 पर पारित आदेश अपास्त योग्य ठहरता है।

आदेश

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकण संख्या 966 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मूल रेकार्ड के साथ तहसीलदार करेड़ा को भेजकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुलिया में स्थिति आराजी संख्या 191 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1858/1828 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा आराजियात का राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार अपीलान्त के नाम अमलदरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को सरेइजलारा सुनाया गया।


(राजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखंड अधिकारी पवेन
उपखण्ड अधिकाारी पवेन करेड़ा कलक्टर
करेड़ा